International Journal of Information Technology and Management
Vol. 18, Issue No. 2, August-2023, ISSN 2249-4510

गरीबी उन्मूलन योजनाओ की प्रभाशीलता

Ruchi Soni[1]*, Dr. Ravi Prakash Pandey[2], Dr. Prabhakar Singh[3]

[1] Research Scholar of Commerce, A.P.S. University Rewa, Madhya Pradesh.

[2] Prof. of Commerce, Sarda Mahavidyalaya Sarlanagar, Maihar, Madhya Pradesh.

[3] Prof. of Commerce, S.G.S. Govt. Auto. P.G. College Sidhi, Madhya Pradesh

सार – *वर्षों से ग्रामीण विकास को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के एक विशिष्ट समूह के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई रणनीति के रूप में विलय कर दिया गया है। हालाँकि, गरीबी को अलग करके बेरोजगारी की समस्या से निपटना कठिन है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बेरोजगारी कम करने में प्रमुख बाधा रही है। इसलिए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को बेरोजगारी कम करने के प्रयासों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। गरीबी की प्रारंभिक परिभाषाएँ पर्याप्त भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतें प्राप्त करने में असमर्थता पर केंद्रित थीं। सीधी जिला मध्य प्रदेश राज्य के गौरवशाली इतिहास का प्रतिबिंब है। यह राज्य की उत्तर–पूर्वी सीमा बनाती है। अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का विश्लेषण करना और राष्ट्रीय स्तर के साथ–साथ राज्य स्तर पर रोजगार पैदा करने में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की भूमिका का मूल्यांकन करना था। अध्ययन में उन सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का पता लगाने का प्रयास किया गया जिनका समग्र गरीबी की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।*

कीवर्ड – *रोजगार, अर्थव्यवस्था, बीपीएल, ग्रामीण, विकास, बेरोजगार*

----------X----------

परिचय

ग्रामीण क्षेत्र के विकास का मतलब न केवल क्षेत्र का समग्र विकास है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भी विकास है। विकास के उद्देश्यों में प्रति व्यक्ति उत्पादन और आय में निरंतर वृद्धि, उत्पादक रोजगार का विस्तार और विकास के लाभों के वितरण में अधिक समानता शामिल है। वर्षों से ग्रामीण विकास को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के एक विशिष्ट समूह के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई रणनीति के रूप में विलय कर दिया गया है।

गरीबी और बेरोजगारी दो प्रमुख मुद्दे हैं जो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के विकास का सामना करते हैं। भारत जैसे देश में गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की चिंता का महत्वपूर्ण विषय रहा है। विशेष रूप से, अधिशेष श्रम वाली अर्थव्यवस्था में युवाओं के लिए श्रोजगार सृजनश का महत्व अधिक हो गया है।

गरीबी की अवधारणा एवं परिभाषा

गरीबी की प्रारंभिक परिभाषाएँ पर्याप्त भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतें प्राप्त करने में असमर्थता पर केंद्रित थीं। आज, मुख्य ध्यान भौतिक अभावों पर बना हुआ है, यानी, निजी संसाधनों पर कब्जा करने में विफलता।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

सीधी जिला मध्य प्रदेश राज्य के गौरवशाली इतिहास का प्रतिबिंब है। यह राज्य की उत्तर–पूर्वी सीमा बनाती है। सीधी जिला प्राकृतिक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का भण्डार है। यह जिला प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, यहां से सोन नदी बहती है।

ऐतिहासिक परिचय

सीधी मध्य प्रदेश का हिस्सा है. यह राज्य की उत्तरपूर्वी सीमा बनाती है। सीधी अपने प्राकृतिक वातावरण, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक जड़ों के लिए जाना जाता है। सीधी में कई प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें सोन नदी जिले को बहाती है, और कोयले का भंडार है जो देश भर के प्रमुख उद्योगों को पोषण देता है।

भौगोलिक परिचय

सीधी जिला मध्य प्रदेश के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित है। यह राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 632 किमी और सर्कल मुख्यालय रीवा से 80 किमी की दूरी पर है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिचय

इस पक्ष के अन्तर्गत जिले में साक्षरता, आयु वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं आदिवासियों का अध्ययन किया जाता है। सीधी जिले में साक्षरता का प्रतिशत 64.43 प्रतिशत है, जो 2001 में 55.27 प्रतिशत था। पुरुष साक्षरता जहाँ 2001 में 69.29 प्रतिशत थी, वहीं 2011 में बढ़कर 74.44 प्रतिशत हो गई।

सारणी क्रमांक 1 सीधी जिले में साक्षरता का वितरण 2001 एवं 2011

www.ignited.in

	वर्ष	सीधी	चुरहट	रामपुर नैकिन	मऔली	कुसमी	सिंहावल	कुल साक्षरता जिला
कुल साक्षरता प्रतिशत	2001	59.55	61.12	56.32	53.59	43.94	54.74	
	2011	67.00	66.82	64.49	63.56	58.31	62.9	64.43
पुरूष साक्षरता प्रतिशत	2001	72.49	75.05	69.74	67.76	57.76	70.24	
	2011	76.12	77.55	79.93	73.47	67.22	74.37	74.44
महिला साक्षरता प्रतिशत	2001	45.34	46.39	42.09	38.54	29.39	38.72	
	2011	57.26	56.19	54.64	53.18	49.17	51.31	54.07

स्रोतरू प्राथमिक डेटा

राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रशासनिक ढाँचां

मध्यप्रदेश राज्य के सीधी जिले का मुख्यालय सीधी नगर में है। सीधी नगर में जिला का कलेक्टर एवं जिले के अन्य सभी कार्यालय हैं। सीधी जिले के विभिन्न विकास कार्यों को मानीटरिंग एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये एक डिप्टी कलेक्टर स्तर का अधिकारी नियुक्त है।

साहित्य की समीक्षा

भारत में, गरीबी की सीमा को मापने के लिए और सुधार–पूर्व अवधि से लेकर सुधार–पश्चात अवधि तक गरीबी की घटनाओं में हुए परिवर्तन को रेखांकित करने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं।

गरीबी और बीपीएल परिवारों का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ समूह

गरीबी एक दीर्घकालिक सामाजिक बीमारी है. इस समस्या से बाहर निकलने के लिए कई नागरिक समाजों के साथ–साथ सरकारें भी बेचौनी से काम कर रही हैं। इसे ख़त्म करने के लिए कई अर्थशास्त्री लंबे समय से काम कर रहे हैं।

गरीबी आकलन और उन्मूलन अध्ययन पर साहित्य

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में गरीबी पर साहित्य विशाल है। कई योगदान या योगदान के संदर्भ निम्नलिखित अध्ययनों में पाए जा सकते हैं – श्रीनिवासन और बर्धन (1974, 1988), फील्ड्स (1980), तेंदुलकर (1998), डिएटन और ड्रेज़ (2002), भल्ला (2002) और डिएटन और कोज़ेल (2005)। पनगढ़िया (2008) ने अपनी प्रकाशित पुस्तक श्इंडियारू द इमर्जिंग जाइंटश में 2000 के दशक के मध्य तक इस विषय पर एक समावेशी कार्रवाई प्रस्तुत की है, जिसमें इस बात पर बहस भी शामिल है कि सुधार के बाद के युग में गरीबी में गिरावट आई थी या नहीं और क्या सुधार हुए थे या नहीं।

राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन पर साहित्य

असवाले, संजय. (2011). 21वीं सदी में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय मुख्य शब्द – घरेलू अर्थव्यवस्था, गरीबी – गरीबी उन्मूलन योजनाएं – योजनाओं का प्रभाव – 2050 के लिए उपाय और रणनीति परिचयरू जुलाई 2008 तक, विश्व की जनसंख्या 6.684 अरब से अधिक होने का अनुमान है जिसमें से एशिया और प्रशांत क्षेत्र की आबादी 3.8 अरब यानी दुनिया की 50 प्रतिशत आबादी है। इस क्षेत्र में दुनिया में सबसे अधिक गरीब लोगों की संख्या वाले 10 देशों में से 7 भी शामिल हैं। जहां तक भारत का सवाल है, 2001 में भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी और विकास दर 1.9 प्रतिशत है। 2007 में गरीबी की दर 19.3 प्रतिशत थी। 2007 में भारत में गरीब लोगों की संख्या 49 मिलियन थी।

अखिलेशचंद्र (2014) ग्रामीण विकास हस्तक्षेपों के महत्वपूर्ण विश्लेषण के बारे में वर्तमान अध्ययन से विभिन्न कारकों का पता चला है जिन्हें क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संशोधित और परिवर्तित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास हस्तक्षेप ग्रामीण विकास के उत्थान के लिए एक स्वस्थ आधार बनाते हैं। ग्रामीण लोगों को विभिन्न रोजगार के अवसर और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके।

क्षेत्रीय स्तर के अध्ययन पर साहित्य

सिंह, प्रमोद और चुडासमा, हरपालसिंह। (2019)। विकासशील देशों में गरीबी की बहुआयामी प्रकृति को संबोधित करने के लिए विभिन्न भागीदारी और समुदाय–मांग–संचालित दृष्टिकोण अपनाए गए हैं।

श्रीवास्तव, डी. और सान्याल, (2007) यह अध्ययन 11 जिलों में फैले 2208 ग्रामीण परिवारों के क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर मध्य प्रदेश में ग्रामीण गरीबी की घटनाओं की जांच करता है।

यादव, राम और सिन्हा, भास्कर। (2021)। वर्तमान अध्ययन में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और मंडला जिलों के उनतीस गांवों में फैले 325 घरों के दो सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले सूचकांकों अर्थात् गरीबी से बाहर प्रगति सूचकांक (पीपीआई) और अभाव से बाहर प्रगति सूचकांक (पीडीआई या डीआई) का उपयोग करके गरीबी का आकलन करने का प्रयास किया गया है। , भारत।

गरीबी उन्मूलन योजना

रोजगार सृजन कार्यक्रम

ऐसे कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं जो गरीब समाज के लिए रोजगार पैदा करते हैं। ये कार्यक्रम गरीब वर्ग को निश्चित अवधि के लिए नियोजित करके और भविष्य में उनके काम के लिए कौशल पैदा करके पूरे समाज के उन्नयन में मदद करते हैं।

स्व–रोज़गार कार्यक्रम

पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन प्रमुख चिंता बनी रही, विभिन्न क्षेत्रीय गतिविधियों के एकीकरण के माध्यम से स्व–रोज़गार कार्यक्रमों को व्यापक बनाने के प्रयास किए गए।

कृषि–सेवा केंद्र

चौथी योजना में बेरोजगार स्नातकों एवं डिप्लोमा धारकों को कृषि–सेवा केन्द्र खोलने के लिए सहायता प्रदान की गई। इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैंरू तकनीकी श्रमिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना; किसानों को उनके कृषि स्थलों पर ही कृषि मशीनरी और उपकरणों के रखरखाव और

www.ignited.in

मरम्मत की सुविधाएं प्रदान करना; स्पेयर पार्ट्स, ईंधन, चिकनाई वाले तेल और अन्य इंजीनियरिंग इनपुट के लिए सुविधाजनक केंद्र स्थापित करना; उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे इनपुट प्रदान करना।

वेतन–रोज़गार कार्यक्रम

मजदूरी–रोज़गार कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कम कृषि मौसम के साथ–साथ सूखे और बाढ़ के दौरान आजीविका प्रदान करना है। मजदूरी–रोजगार कार्यक्रम पहली बार छठी और सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) के रूप में शुरू किए गए थे।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

1- सीमांत किसान विकास एजेंसियां (एमएफडीए)

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) का एक उद्देश्य छोटे किसानों को ऋण प्रदान करना था ताकि वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सकें और गहन खेती को अपना सकें। योजना आयोग के निर्देश पर छोटे निर्माताओं की पहचान करने और छोटे निर्माताओं की वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए बैंकों को विभिन्न योजनाएँ प्रस्तुत करने के लिए ऐसी एजेंसियों की स्थापना की गई थी।

खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम

1- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

इस योजना के प्रावधानों के अनुसार गरीब लोगों को 4 लाख उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है ताकि उन्हें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुछ राज्यों में यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की गई है। इस योजना पर सरकारी बजट का लगभग 3 प्रतिशत खर्च किया जाता है।

प्रतिदर्शित परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से देश की गरीबीग्रस्त स्थिति में योगदान देने वाला मुख्य कारक अत्यधिक जनसंख्या की समस्या है।

सामाजिक स्थिति

गरीबी की समस्या के बने रहने के पीछे कई आर्थिक कारण हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है –

कृषि अवसंरचना –

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन पुरानी कृषि पद्धतियों, उचित सिंचाई बुनियादी ढांचे की कमी और यहां तक कि फसल प्रबंधन के औपचारिक ज्ञान की कमी ने इस क्षेत्र में उत्पादकता को काफी प्रभावित किया है।

परिसंपत्तियों का असमान वितरण –

अर्थव्यवस्था की दिशाएँ तेजी से बदलने के साथ, विभिन्न आर्थिक आय समूहों में कमाई की संरचना अलग–अलग तरह से विकसित होती है। उच्च और मध्यम आय समूहों की आय में निम्न आय समूहों की तुलना में तेजी से वृद्धि देखी गई है।

बेरोजगारी –

एक अन्य प्रमुख आर्थिक कारक जो देश में गरीबी का कारण है, वह है बढ़ती बेरोजगारी दर। भारत में बेरोजगारी दर अधिक है और 2015 के सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर, 77% परिवारों के पास आय का नियमित स्रोत नहीं है।

मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि –

मुद्रास्फीति शब्द को मुद्रा के क्रय मूल्य में गिरावट के साथ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, भोजन, कपड़े की वस्तुओं के साथ–साथ अचल संपत्ति की प्रभावी कीमत बढ़ जाती है।

दोषपूर्ण आर्थिक उदारीकरण –

1991 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एलपीजी (उदारीकरण–निजीकरण–वैश्वीकरण) प्रयासों को विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय बाजार–रुझानों के लिए अधिक अनुकूल बनाने की दिशा में निर्देशित किया गया था।

आर्थिक स्थति

देश को परेशान करने वाले विभिन्न सामाजिक मुद्दे जो गरीबी में योगदान करते हैं वे हैंरू –

शिक्षा एवं अशिक्षा –

शिक्षा, बल्कि इसकी कमी और गरीबी एक दुष्चक्र का निर्माण करती है जो राष्ट्र को परेशान करती है।

अप्रचलित सामाजिक रीति–रिवाज –

जाति व्यवस्था जैसे सामाजिक रीति–रिवाज समाज के कुछ वर्गों के अलगाव और हाशिए पर जाने का कारण बनते हैं।

कुशल श्रमिकों की कमी –

पर्याप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी भारत में उपलब्ध विशाल श्रम शक्ति को काफी हद तक अकुशल बनाती है, जो अधिकतम आर्थिक मूल्य प्रदान करने के लिए अनुपयुक्त है।

लैंगिक असमानता–

महिलाओं से जुड़ी कमजोर स्थिति, गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक हाशिये की स्थिति और घरेलूता की लंबे समय से अंतर्निहित धारणाएं देश की लगभग 50% आबादी को काम करने में असमर्थ बनाती हैं।

भ्रष्टाचार –

www.ignited.in

गरीबी की स्थिति को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं के रूप में सरकार के काफी प्रयासों के बावजूद, देश में भ्रष्टाचार की व्यापक प्रथाओं के कारण कथित तौर पर केवल 30.35% ही वास्तव में लाभार्थियों तक पहुंच पाता है।

दीर्घकालिक और क्षणिक गरीबी की व्यापकता और जनसांख्यिकी

सीधी में गरीबी की अवधि पर पहले के शोध में बड़े पैमाने पर केवल 1960 से 1980 के दशक के डेटा की जांच की गई है, और डेटा सीमाओं के कारण कुछ प्रमुख जनसांख्यिकीय समूहों, विशेष रूप से हिस्पैनिक्स और सामान्य रूप से आप्रवासियों को बाहर रखा गया है।

अध्ययन की समय–सीमा के दौरान समग्र नमूने के एक बहुत छोटे हिस्से ने पुरानी गरीबी का अनुभव किया। समग्र दीर्घकालिक गरीबी दर 2.1% (सीआई 1.4%, 2.8%½ थी, जो लगभग 50 व्यक्तियों में से एक के बराबर थी। इसके विपरीत, समग्र नमूने में क्षणिक गरीबी काफी सामान्य थी। समग्र क्षणिक गरीबी दर 18.9% थी (सीआई 17.3%, 20.4%); इस प्रकार, अध्ययन की समय सीमा के दौरान क्षणिक गरीबी ने पांच में से लगभग एक व्यक्ति को प्रभावित किया।

तालिका 2 जनसांख्यिकीय उपसमूहों के लिए दीर्घकालिक और क्षणिक गरीबी दर.

जनसांख्यिकीय उपसमूह	क्षणिक गरीबी दर	(से) [95% सीआई] (से)	उपसमूह % के रूप में दर के लिए दर कुल मिलाकर नमूना	दीर्घकालिक गरीबी दर	(se) [95% CI]	उपसमूह % के रूप में दर के लिए दर कुल मिलाकर नमूना
सभी व्यक्ति	**18.9%**	**(0.7) [17.3, 20.4]**		**2.1%**	**(0.4) [1.4, 2.8]**	
आधार रेखा पर आयु 18 से 54 वर्ष (कार्यरत- आयु वयस्क संपूर्ण अवधि)	16.5%	(0.9) [14.7, 18.2]	87%	1.6%	(0.3) [1.0, 2.2]	76%
आधार रेखा पर आयु 0 से 7 (बच्चा संपूर्ण) अवधि)	20.6%	(1.8) [17.1, 24.1]	109%	2.5%	(0.8) [0.8, 4.2]	119%
आधार रेखा पर आयु 65 (वरिष्ठ संपूर्ण) अवधि)	24.2%	(2.4) [19.2, 29.1]	128%	5.1%	(1.2) [2.8, 7.5]	243%
हिस्पैनिक परिवार का मुखिया	37.5%	(3.8) [29.9, 45.1]	198%	9.8%	(3.1) [3.5, 16.0]	467%
काले घर का मुखिया	31.0%	(2.1) [26.7, 35.4]	164%	4.0%	(0.6) [2.8, 5.2]	190%
श्वेत परिवार का मुखिया	15.1%	(0.7) [13.6, 16.5]	80%	1.5%	(0.9) [-0.3, 3.2]	71%
अन्य जाति परिवार का मुखिया	15.0%	(3.3) [8.4, 21.6]	79%	0.9%	(0.2) [0.6, 1.2]	43%
अप्रवासी परिवार	33.2%	(3.8) [25.4, 41.0]	176%	10.2%	(3.2) [3.7, 16.6]	486%
घर में 0 से 17 वर्ष की आयु का बच्चा आधे से अधिक वर्ष	19.3%	(1.3) [16.8, 21.9]	102%	2.2%	(0.6) [0.9, 3.5]	105%
गैर-हाई स्कूल स्नातक मुखिया/पत्नी/सहवासी	36.2%	(2.7) [30.7, 41.6]	192%	8.9%	(1.9) [5.0, 12.7]	424%
सभी व्यक्ति	**18.9%**	**(0.7) [17.3, 20.4]**		**2.1%**	**(0.4) [1.4, 2.8]**	
कोई कामकाजी मुखिया/पत्नी/सहवासी नहीं - कम से कम एक वर्ष	35.9%	(1.6) [32.7, 39.1]	190%	5.6%	(0.6) [4.3, 6.9]	267%
कार्यकारी मुखिया/पत्नी/सह-साथी - सभी साल	13.3%	(0.8) [11.7, 14.9]	70%	0.9%	(0.4) [0.1, 1.7]	43%
बेरोजगार (काम की तलाश में) मुखिया/पत्नी/सहवासी - कुछ के लिए वर्ष की अवधि कम से कम एक के दौरान वर्ष	24.1%	(1.4) [21.3, 27.0]	128%	2.9%	(0.8) [1.2, 4.5]	138%
विकलांग मुखिया/पत्नी/सहवासी - पर कम से कम एक वर्ष	30.4%	(1.5) [27.3, 33.5]	161%	4.5%	(0.7) [3.1, 5.9]	214%
एकल माँ परिवार - कम से कम एक वर्ष	34.2%	(2.9) [28.5, 40.0]	181%	3.1%	(0.8) [1.5, 4.7]	148%
उच्च लागत वाला आवास क्षेत्र - से अधिक आधे साल	19.9%	(2.0) [15.9, 23.9]	105%	3.4%	(1.2) [1.0, 5.9]	162%
शहरी/उपनगरीय (एमएसए में)	17.1%	(0.9) [15.2, 18.9]	90%	1.8%	(0.6) [0.6, 3.0]	86%
ग्रामीण (एमएसए के बाहर)	21.0%	(1.4) [18.1, 23.9]	111%	1.9%	(0.4) [1.1, 2.8]	90%
क्षेत्र पश्चिम	21.5%	(2.2) [17.0, 26.0]	114%	4.1%	(1.4) [1.3, 6.9]	195%

www.ignited.in

क्षेत्र पश्चिम	21.5%	(2.2) [17.0, 26.0]	114%	4.1%	(1.4) [1.3, 6.9]	195%
क्षेत्र दक्षिण	20.9%	(1.2) [18.6, 23.3]	111%	2.2%	(0.4) [1.3, 3.0]	105%
क्षेत्र मिडवेस्ट	17.5%	(1.5) [14.4, 20.6]	93%	1.2%	(0.3) [0.5, 1.8]	57%
क्षेत्र पूर्वोत्तर	14.7%	(1.5) [11.7, 17.7]	78%	0.9%	(0.3) [0.3, 1.5]	43%

सभी व्यक्ति	**18.9%**	**(0.7) [17.3, 20.4]**		**2.1%**	**(0.4) [1.4, 2.8]**	
किराये पर लेनेवाला	34.9%	(1.9) [31.1, 38.7]	185%	5.5%	(0.8) [3.8, 7.2]	262%
बंधक के बिना गृहस्वामी	21.9%	(1.7) [18.5, 25.3]	116%	2.1%	(0.6) [1.0, 3.3]	100%
बंधक वाला गृहस्वामी	11.8%	(0.9) [10.0, 13.5]	62%	0.8%	(0.5) [-0.2, 1.7]	38%
बीमा रहित घर	60.8%	(5.2) [50.2, 71.3]	322%	10.1%	(3.3) [3.6, 16.7]	481%

सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा परिवार	37.1%	(2.3) [32.6, 41.6]	196%	9.9%	(1.7) [6.5, 13.3]	471%
निजी स्वास्थ्य बीमा घरेलू	13.8%	(0.7) [12.4, 15.2]	73%	0.3%	(0.1) [0.1, 0.4]	14%

निष्कर्ष

अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का विश्लेषण करना और राष्ट्रीय स्तर के साथ–साथ राज्य स्तर पर रोजगार पैदा करने में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की भूमिका का मूल्यांकन करना था। अध्ययन में उन सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का पता लगाने का प्रयास किया गया जिनका समग्र गरीबी की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से, अध्ययन में वित्तीय विविधताओं के सबूत खोजने का प्रयास किया गया जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के भौतिक प्रदर्शन को व्यवस्थित रूप से प्रभावित करते हैं। गरीबी–विरोधी कार्यक्रमों का निर्माण गरीबी की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, हालाँकि इस दिशा में प्रमुख भूमिका इन कार्यक्रमों द्वारा निभाई जाती है। गरीबों की पहचान का काम स्थानीय सरकार को सौंपा जाना चाहिए। गरीबी के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न–भिन्न होते हैं। इसलिए गरीबी के कारणों और उपायों की स्थानीय पहचान होनी चाहिए। संपूर्ण राज्यों को कवर करने वाले व्यापक आधारित दृष्टिकोण दुर्लभ संसाधनों को सबसे कुशल तरीके से उपयोग करने में सक्षम नहीं बनाते हैं। किसी भी क्षेत्र में लागू करने के लिए सबसे प्रभावी सार्वजनिक नीतियों की पहचान सावधानीपूर्वक सूक्ष्म स्तर के विश्लेषण के माध्यम से की जाती है।

संदर्भ

1. पांडा, सीताकांत। (2014)। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में राजनीतिक संबंध और अभिजात वर्ग का कब्जा। विकास अध्ययन जर्नल. 51- 50&65- 10-1080/00220388-2014-947281-

2. मंडल, सौम्यब्रत और कुमार, विनय और साहू, प्रियब्रत। ¼2023½। ग्रामीण भारत में बहुआयामी अभावरू एक राज्य–स्तरीय विश्लेषण। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. 58- 37&45-

3. सतपथी, स्वास्तिक और जयसवाल, कृष्णा। (2018)। भारत में गरीबी अनुमान और गरीबी की वर्तमान स्थिति पर एक अध्ययन।

4. सिगेल, एकहार्ड. (2010)। भारत में गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सुधार। विकास अध्ययन में प्रगति – प्रोग्र देव स्टड। 10- 247&259- 10-1177/146499340901000304A

5. कुमार, संजीव. (2022)। भारत में ग्रामीण परिवर्तन.

6. मल्लिक, परमेश्वर और पलटासिंह, तत्त्वमसि। (2023)। हाशिये पर पड़े वर्गों पर मनरेगा की प्रभावशीलता हाशिये पर पड़े वर्गों पर मनरेगा की प्रभावशीलतारू संदर्भ और संभावनाएँ। 45- 171&190-

7. दास, पिनाकी और चोश, सुदेशना और पारिया, बिबेक। (2023)। भारत में बहुआयामी गरीबीरू 2005&06 और 2019&21 के दौरान जनसंख्या उपसमूहों और भौगोलिक स्थानों में कमी के पैटर्न। जियोजर्नल। 88-1&20- 10-1007/,l10708&023&10833&6A

8. गर्ग, शुभम और प्रियंका, प्रियंका और नरवाल, करम। (2023)। मैक्रो स्तर पर भारत में मुद्रा योजना का महत्वपूर्ण मूल्यांकनरू एक अनुभवजन्य अध्ययन। 71-48&54-

Corresponding Author

Ruchi Soni*

Research Scholar of Commerce, A.P.S. University Rewa, Madhya Pradesh

www.ignited.in